>

Title: Regarding alleged scam in allotment of Coal box in the country.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि कल देश की सर्वोच्च अदालत का सरकार को एक तरह से मैसेज आया है, मैं उसे सलाम करता हूं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कोल ब्लाक्स के आबंटन को लेकर 1,86,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया था। केन्द्र सरकार को देश की जनता ने चुना है और जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन आप खुद ही खड़े नहीं होते। मैं यह नहीं मानता कि सरकार काम करती है तो उससे गलती न हो। सवाल यह है कि अगर गलती हो जाए तो सरकार कितनी जल्दी उस गलती को स्वीकार करती है और कैसे उस पर तत्काल कार्यवाही करती है।

मैंने इस मामले को कितनी ही बार यहां उठाया है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जी से भी कहा है कि जिन पार्टियों के लोग हैसियत में हैं और जिनका नाम इसमें आया है, जिन्होंने एक चौथाई कोल ब्लाक्स लिए हैं, यहां बड़े पदों पर हैं, वे अहम् पदों पर नहीं रहने चाहिए। एक काम जरूर हुआ है कि एक आदमी जो बड़े पद पर था, उसका इसमें नाम आया तो उसे नीचे कर दिया गया, उस पर आपने एक्शन लिया।

इससे पहले अदालत ने 2जी मामले में भी सरकार को संदेश दिया था। यह कितनी बड़ी बात है कि अदालत ने सीबीआई को यह कहा कि आपको सरकार से सलाह नहीं करनी है। इससे एक विश्वास टूट गया है, यह विश्वास लोकतंत्र का है। जनता द्वारा चुने हुए हम प्रतिनिधि हैं और हम सरकार बनाते हैं इसलिए सारी चीजें हमें करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बात कहनी पड़ती है, वह कहना नहीं चाहती, लेकिन तो उनका मन भी व्यथित है और इसी कारण अदालत को यह कहना पड़ता है कि आपसे सलाह की जरूरत नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

सीबीआई ने भी अच्छा काम किया है और बताया है कि इसमें गड़बड़ हुई है। कोल ब्लाक्स इस तरह बांटे गए हैं जैसे रेल के टिकट या सिनेमा के टिकट बांटे जाते हैं, इस तरह से एलाट किए गए हैं। अब देश के सामने सरकार सफाई दे रही है, वित्त मंत्री जी सफाई दे रहे हैं। हमारे देश में कोल तीसरे नम्बर की खनिज सम्पदा है। आइरन ओर से लेकर कोल आदि कई खनिज हमारे देश में हैं। इन सारी चीजों के बावजूद यह देश कमजोर है।

जसवंत सिंह जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अभी एक मामला यहां उठाया था। कोई एक मामला नहीं है। दुनिया में हमारी कोई नहीं सुनता है। यदि हमने अपने को मजबूत और ताकतवर किया होता, अपने देश के संसाधनों को ठीक से युटिलाइज किया होता तो यह स्थिति नहीं होती और दुनिया में हमारी इज्जत होती। आज चीन के सामने कोई देश सिर नहीं उठा सकता, जबकि हमारे सामने हर कोई सिर उठाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वह बताए कि सरकार देश चला रही है या अदालतें चला रही हैं। इसलिए आप खड़े हों और इस पर निर्णय करें। सरकार को कई बार जोखिम उठाकर भी फैसले करने पड़ते हैं, उन फैसलों से नुकसान हो सकता है, लेकिन देश का भविष्य बनता है। इसलिए प्रधान मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप खड़े हों और इस पर जवाब दें। मान लें कि आपके अनुमान में कोई गलती हो गई है, तब भी देश की सम्पति बचाने के लिए कड़े कदम उठाकर सारे कोल ब्लाक्स कैंसिल करने चाहिए और नया मैसेज देश के समाने देना चाहिए।

यही मेरी आपसे विनती है।

अध्यक्ष महोदया:

श्री देवजी एम. पटेल,

श्री बंस गोपाल चौधरी,

श्री एम.बी. राजेश,

श्री पी.के. बीजू,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री रामसिंह कस्वां और

प्रो. रामशंकर, माननीय सदस्य शरद यादव जी द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।